फरीदाबाद

मजदूर समाचार

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा

नई सीरीज नम्बर 89 नवम्बर 1995

इस अंक में

- जबरन वसूली
- केल्विनेटर एग्रीमेंट
- बिजली बोर्ड हड़ताल
- जागरण वालों से निवेदन
- पेन्शन स्कीम

मैनेजमेन्टों के दबदबे के दौर में

मालिक - मालिक - मालिक की रट (1)

★ **कम्पनी :** दूर-दराज के व्यापार में मुनाफा अधिक था परन्तु यह खर्च बहुत माँगता था जो कि इक्के-दुक्के के बस से बाहर का था इसलिये चार-पाँच सौ साल पहले ही इस क्षेत्र में कम्पनियाँ बन गई थी – ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी, फ्रेन्च ईस्ट इंडिया कम्पनी आदि-आदि। बढते व्यापार की जरूरतों ने दस्तकारी-शिल्पी उत्पादन को धकेल कर फैक्ट्री प्रोडक्शन को जन्म दिया। हालाँकि भाप-कोयले के दबदबे के दौर में भी रेलवे निर्माण व संचालन जैसा खर्च इक्के-दुक्के के बूते के बाहर था इसलिये इनके लिये भी कम्पनियाँ बनी परन्तु भाप-कोयले के सुनहरे काल में फैक्ट्री प्रोडक्शन सारतः इस पैमाने का था कि उसका खर्च अमीर व्यक्ति उठा सकता था इसलिये फैक्ट्रियाँ आमतौर पर इस या उस मालिक की होती थी। भाप-कोयले के दबदबे के दौर में ही हालाँकि इतनी विशाल मशीनें और विराट फैक्ट्रियाँ बनने लगी थी कि उनके लिये आवश्यक साधन जुटाने के लिये कम्पनियों का गठन जरूरी हो गया था फिर भी, यह बिजली-तेल का दौर है जिसमें प्रोडक्शन क्षेत्र में बड़े पैमाने के खर्च की जरूरत ने कम्पनियों के गठन को एक अनिवार्य आवश्यकता बनाया। आज व्यापार, ट्रान्सपोर्ट, प्रोडक्शन में ही नहीं बल्कि शिक्षा - ट्रेनिंग - रिसर्च - प्रचार - मनोरंजन - राजनीति के क्षेत्रों में भी कम्पनी - बोर्ड - कारपोरेशन - पार्टी अनिवार्य आवश्यकता बन गई हैं। बिजनेस के हर क्षेत्र में कम्पनियाँ धुरी बन गई हैं।

★ **कम्पनी और मैनेजमेन्ट :** प्रोडक्शन क्षेत्र की कम्पनियों में आरम्भ में गिने-चुने लोगों के पैसे लगे होते थे। बड़े हिस्सेदार कम्पनी के डायरेक्टर बनते थे और फैक्ट्री के काम-काज में सक्रिय भूमिका अदा करते थे। मालिक न होते हुये भी डायरेक्टर लोग किसी मालिक से ज्यादा भिन्न नहीं थे और व्यवहार वे फैक्ट्री मालिक की ही तरह करते थे। परन्तु कम्पनियों की लाखों से करोड़ों - अरबों - खरबों के दायरों में जाती आवश्यकता की प्रक्रिया में लखपति बौने होते गये। फैक्ट्रियों में लगते पैसों में बैंक - बीमा - इनवैस्टमैन्ट कम्पनियों के बढ़ते हिस्से ने व्यक्ति - कुल के नाम को मात्र सजावट की वस्तु में बदला।

आज किसी फैक्ट्री के निर्माण व संचालन में 100 करोड़ रुपये लगते हैं तो उनका जुगाड़ 5 करोड़ रुपये के शेयरों और 95 करोड़ रुपयों के बैंक - बीमा के कर्ज से किया जाता है। लिमिटेड कम्पनियों में तो शेयरों में भी बड़ा हिस्सा बैंक - बीमा - इनवैस्टमैन्ट कम्पनियों का होता है। और फिर, हजारों फुटकर शेयर होल्डर भी अभी तो होते हैं ही। व्यक्ति-विशेष व परिवार-विशेष द्वारा अपने खुद के पैसों से खरीदे शेयर किसी भी लिमिटेड कम्पनी में एक परसैन्ट भी नहीं होते। वैसे, शेयरों पर कन्ट्रोल के लिये धर्मार्थ ट्रस्ट आदि मुखौटों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी, टाटा - बिड़ला - बजाज - अम्बानी - वाडिया - नन्दा - लोहिया - भरतिया - राजगढिया की कही जाने वाली किसी भी कम्पनी में लगी कुल राशि में इन परिवारों और इनके ट्रस्टों का रुपये में एक पैसे का भी दसवाँ हिस्सा मुश्किल से होता है।

कम्पनियों के संचालन के लिये मैनेजमेन्टें हैं और आज भी मैनेजमेन्ट का शीर्ष बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। लेकिन प्रारम्भ के बोर्ड और आज के बोर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो यह है कि किसी भी कम्पनी में लगी कुल राशि का प्रमुख अंश अब कर्ज के रूप में होता है – हर वक्त मौजूद कर्ज का भूत तभी प्रकट होता है जब कोई कम्पनी लड़खड़ाती है। दूसरी बात यह है कि बैंक - बीमा - इनवैस्टमैन्ट कंपनियों का शेयरों में बहुमत होते हुये भी यह आमतौर पर किसी कम्पनी का संचालन स्वयं नहीं करते और जब तक कोई कम्पनी दुधारू रहती है तब तक कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके प्रतिनिधि स्लीपिंग, यानि सोये हुओं की मुद्रा में रहते हैं। कम्पनी डायरेक्टरों की मीटिंगें आमतौर पर रस्मी होती हैं और बोर्ड की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर कर्ता-धर्ता की भूमिका अदा करते हैं। यानि, किसी फैक्ट्री में लगी कुल राशि में जिनका हजारवाँ अंश भी नहीं होता वे एम डी के रूप में मैनेजमेन्ट प्रमुख का रोल निभाते हैं। ऐसे चेयरमैन - एम डी को मालिक कहने का रिवाज मजदूरों की सोच-विचार-व्यवहार को गड़बड़ाता है। व्यक्ति-विशेष के गुणों-अवगुणों पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है। जबकि, कम प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि अधिक प्रोडक्शन भी आफतें लिये है और कोई चीज कब कम है तथा कब ज्यादा यह अब उसकी मात्रा से तय नहीं होता और न ही किसी भी व्यक्ति, किसी भी मैनेजमेन्ट, किसी भी कम्पनी, किसी भी सरकार द्वारा यह तय किया जा सकता बल्कि इन सब के काबू से बाहर विश्व मन्डी है जो यह तय करती है। तीसमारखाँओं के लाख किस्से प्रचार में हैं परन्तु वास्तव में मैनेजिंग डायरेक्टर के जीनियस होने अथवा औसत होने से कम्पनी की हालात पर उल्लेखनीय असर नहीं पड़ता। चौतरफा फैला और गहरा रहा असन्तोष लक्षण है विगत में बेगार-प्रथा की तरह वर्तमान में मजदूरी-प्रथा के लड़खड़ाने लगने का। परन्तु, व्यक्ति-विशेष अथवा मैनेजमेन्ट-विशेष को कम्पनी के लड़खड़ाने के जिम्मेदार ठहराना खोखली हो गई मजदूरी-प्रथा की इस हकीकत को छिपाता है और रिजर्व बैंकों को मिसमैनेजमेन्ट - कुप्रबन्ध वाले विलाप राग छेड़ने के अवसर देता है।

★ **मैनेजिंग डायरेक्टर :** मैनेजमेन्टों का नामकरण मैनेजिंग डायरेक्टर से अथवा एम डी जिस ग्रुप का है उसके अनुसार होता है, यथा नन्दा - टाटा - बिड़ला - बजाज - आई टी सी - आई बी एम मैनेजमेन्ट। मामूली औकात वाली पोजीशन का इतना नाम क्यों है? किसी कम्पनी के एम डी पद के लिये इतनी उठा-पटक क्यों होती है? प्रधानमन्त्री-मुख्यमंत्री की कैटेगरी का होता है कम्पनी का एम डी। तनखा, सहुलियतें, ताम-झाम तो होते ही हैं पर यह गौण हैं। वैसे, संस्थागत ढाँचों के मजबूत होते जाने के साथ व्यक्ति इतने गौण होते जा रहे हैं कि अन्य लोगों की तुलना में अधिक ताकत और ख्याति व्यक्तित्व की मृगमरीचिका बन गये हैं। परन्तु असल वजन वाली बात है खरीद और बिक्री में कमीशन : सेनापति दो हजार करोड़ रुपये की तोपों की खरीद में दस परसैन्ट कमीशन के तौर पर 200 करोड़ रुपये लेता है और कोयला मन्त्री 1200 रुपये टन भाव का कोयला 1000 रुपये टन में बेच कर 80 करोड़ रुपये जेब में रखता है। कम्पनी की कीमत पर यह दो नम्बर का पैसा बटोरना होता है कि प्रधानमन्त्री - मुख्यमन्त्री - सेनापति - मन्त्री की कुर्सी वाली मारा-मारी कम्पनियों के एम डी पद के लिये, कम्पनियों की मैनेजमेन्ट हथियाने के लिये भी होती है। कम्पनी में लगी कुल राशि का हजारवाँ अँश भी एम डी की जेब से नहीं होता इसलिये कम्पनी के खातों की खानापूर्ति कर, कानूनी चक्करों से बचें कर, दुधारू गाय को स्वस्थ रख कर दो नम्बर के पैसे बनाना आम बात है। बही-खातों, कागज-पत्रों को दुरुस्त रखने के लिये विशेषज्ञ रखे जाते हैं परन्तु फिर भी मैनेजमेन्ट में गुटबाजी अथवा कम्पनी के लड़खड़ाने की स्थिति में जब-तब कानूनों के पालन में किसी एम डी की लापरवाही उजागर होती रहती है और यह अखबारों में हाय-तौबा के लिये मैटेरियल बनती रहती है। असल में, उत्पादन के कम्पनी-स्वरूप में हेरा-फेरी अन्तर्निहित है। लाख विजिलैन्स-सतर्कता विभागों के बावजूद मुहावरे की भाषा में कहें तो हालात अन्धे पीसें कुत्ते खायें वाली हैं।

(बाकी पेज दो पर)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद -121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच है)

मैनेजमेन्टों का दबदबा..... मालिक - मालिक की रट (पेज एक का शेष)

साहब लोगों में प्रायवेट और सरकारी के नाम पर खेमेबन्दी की विश्वव्यापी चीख-चित्कार ने हाल के वर्षों में नये तेवर अख्तियार किये हैं परन्तु प्रायवेट कम्पनी और सरकारी कम्पनी में फर्क करने के लिये उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपको सूई के छेद में से हाथी को निकालना होगा। 19वीं सदी के प्रायवेट और आज के "प्रायवेट" के अर्थ में रात और दिन जितना फर्क है।

★ **फैक्ट्री प्रोडक्शन की हिस्सा-पत्ती :** फैक्ट्रियों-वर्कशॉपों में प्रति मजदूर आज यहाँ एक दिन में आठ घन्टे की शिफ्ट में एक हजार से 15-20 हजार रुपये मूल्य के अर्थ में का नया प्रोडक्शन करवाया जाता है। वरकर को इसके 25 से 200 रुपये, यानि अपने द्वारा पैदा किये रुपयों में से मात्र एक या दो परसैन्ट मिलते हैं। बाकी की हिस्सा-पत्ती सरकारी टैक्स, कर्जे पर ब्याज, शेयर होल्डरों को डिविडेन्ड, व्यापारियों को मार्जिन, मैनेजमेन्ट की शान-शौकत व ताम-झाम और कम्पनी के बही-खातों में जमा - संचय के रूप में होती है।

आज से सौ-सवा सौ वर्ष पहले सबसे शक्तिशाली सरकार के पास भी एक लाख सैनिकों की परमानेन्ट फौज नहीं थी जबकि आज एटम बमों और मिसाइलों की छत्रछाया में भारत सरकार के पास ही हर वक्त 15 लाख परमानेन्ट फौजी और 25 राज्य पुलिस व 25 ही राज्य सशस्त्र पुलिस - सी आर पी - बी एस एफ - आर पी एफ - सी आई एस एफ - आई टी बी पी - आदि-आदि गिरोहबन्दियों में 15-17 लाख अतिरिक्त परमानेन्ट हथियारबन्द लोग हैं। मन्त्री-सन्तरी-अफसर-जेल का यह विशाल तन्त्र हर देश में प्रत्येक मजदूर द्वारा पैदा किये जाते मूल्य के आधे से ज्यादा हिस्से को डकार जाता है। 15 परसैन्ट के करीब बैंक-बीमा कम्पनियों को दिये कर्ज पर ब्याज के रूप में वसूल लेते हैं। दस-बारह परसैन्ट व्यापारी मार्जिन - ट्रान्सपोर्ट - प्रचार के तौर पर काम आता है तो पाँच-सात परसैन्ट शेयरों पर डिविडेन्डों में और इतनी ही मात्रा कम्पनियों के साहबों की शान-शौकत के काम आती है। मजदूर द्वारा पैदा किये मूल्य में से पाँच-सात परसैन्ट संचित होता है, कम्पनियों को बढाता है।

जाहिर है, मजदूरों द्वारा अपने प्रोडक्शन में अपनी हिस्सा-पत्ती बढाने के प्रयास उपरोक्त अन्य हिस्सेदारों पर असर डालेंगे। परन्तु एक बात बिलकुल साफ है, आज यहाँ मजदूर की औसत तनखा एक लाख रुपये महीना हो तो भी मजदूरों को उनके प्रोडक्शन का पूरा नहीं मिलेगा। मजदूरों का अपने प्रोडक्शन में हिस्सा बढने का मतलब है तोप - एटम बम - मिसाइल कम करने पड़ेंगे; ध्याड़ी के लिये मरने और मारने वालों की संख्या कम होगी; बिना बात पर भी थप्पड़ मारने - झाड़ने - गाली देने वाले वर्दीधारी गुन्डों की गिनती कम होगी; बैंकों की ब्याज दर घटेगी; व्यापारियों का मार्जिन कम होगा; मुस्कानें कम बिकेंगी; शेयरों से आमदनी घटेगी; साहबों के फाइव स्टार बिल कम होंगे और उन्हें अपने फुटकर गुन्डों की छँटनी करनी होगी; आदि-आदि। हमें नहीं लगता कि किसी मजदूर को इस पर कोई आपत्ति होगी। और फिर, अपने उत्पादन में अपने हिस्से को बढाने के लिये मजदूरों द्वारा लगातार कोशिश करना पृथ्वी के विनाश के लिये जगह-जगह बन रही पृथ्वी मिसाइलों पर भी रोक लगाता है – इसलिये वरकरों द्वारा अपने जीवन स्तर में सुधार के प्रयास पृथ्वी पर जीवन की रक्षा की सुगन्ध बोनस रूप में लिये हैं।

स्वस्थ तो स्वस्थ, प्रोडक्शन में होती हिस्सा-पत्ती किसी कम्पनी के बीमार होने पर मजदूरों के लिये अतिरिक्त महत्व की बन जाती है। आमतौर पर मैनेजमेन्ट और लीडर कम्पनी के बीमार होने पर खर्च में कटौती के लिये मजदूरों से कुर्बानी माँगते हैं ताकि कम्पनी को स्वस्थ किया जा सके। अपने द्वारा उत्पन्न किये मूल्य में एक-दो परसैन्ट हिस्सा पाते मजदूरों से इस प्रकार की डिमान्ड करना अर्थहीन और बेतुकी बात है। इस सन्दर्भ में टैक्स रूपी सरकारी हिस्से में कमी, बैंक-बीमा की ब्याज दर में कमी, व्यापारियों के मार्जिन में कटौती, शेयर होल्डरों के डिविडेन्ड कम करना और साहब लोगों द्वारा अपनी शान-शौकत में कटौती ही मतलब की हैं और मजदूरों द्वारा इन्हीं कटौतियों की डिमान्ड करना वास्तविकता के अनुरूप कदम उठाना है। इतना ही नहीं, बीमार कम्पनी में अपने वेतन बढवाने के लिये मजदूरों को प्रयास जारी रखने चाहियें क्योंकि कम्पनी बीमार हो चाहे स्वस्थ, मजदूरों का हिस्सा अन्य हिस्सेदारों से खींचा-तान द्वारा ही तय होता है।

★ **कम्पनी का बन्द होना, क्लोजर :** किसी भी कम्पनी का कोई मालिक नहीं होता। कम्पनियाँ जो भी कर्ज लेती हैं वह मशीनों, बिल्डिंगों या जमीनों को गिरवी रख कर लेती हैं। बन्द होने की स्थिति में कम्पनियों की देनदारियों के भुगतान के जरिये भी यही हैं। यह तथ्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि कम्पनी की देनदारी का जिम्मेदार कोई चेयरमैन - मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता।

साथ ही, अन्धे पीसें कुत्ते खायें वाले हालात के दृष्टिगत बैंक अफसरों, प्रोविडेन्ट फन्ड अधिकारियों, ई एस आई अफसरों, बिजली बोर्ड अफसरों को रिश्वतें दे कर कम्पनियों की मैनेजमेन्टें कम्पनी की कुल सम्पत्ति से काफी ज्यादा की देनदार बन जाती हैं। बुलबुला कम्पनी की बीमारी बढने और क्लोजर की स्थिति में फूटता है। इस सिलसिले में यूनियन लीडरों की मिलिभगत आमतौर पर मजदूरों का भी काफी पैसा कम्पनी में फँसा देती है। ऐसे में किसी फैक्ट्री के क्लोजर की स्थिति में मजदूरों द्वारा फैक्ट्री पर कब्जा कर अपने पैसे वसूलने के लिये कदम उठाना जरूरी बनता है।

फैक्ट्री क्लोजर की स्थिति में मजदूर अक्सर लीडरों के कानून-वानून के झाँसों में आ जाते हैं और तब उनका हाल 1983 में बन्द कर दी गई ईस्ट इंडिया की जूट मिल के 900 मजदूरों वाला होता है जिन्हें आज तक हिसाब नहीं मिला है। ऐसे अनुभवों से सीख कर कुछ मजदूरों ने फैक्ट्री क्लोजर की स्थिति में फैक्ट्रियों पर कब्जे किये हैं। प्रारम्भ में हड़बड़ाने के बाद अब इस प्रकार कदम उठा रहे मजदूरों के लिये यहाँ बी आई एफ आर और लीडरों ने "मजदूर खुद फैक्ट्री चलायें" का मीठा फन्दा तैयार किया है। इस फन्दे में फँसने का प्रमुख कारण मजदूरों में इस समझ का हावी होना है कि कम्पनी खूब मुनाफा दे सकती है बस हेरा-फेरी के लिये अथवा खुन्दक में बन्द की जा रही है। जबकि, हकीकत यह है कि दूध की एक धार तक की जब तक गुँजाइश होती है तब तक हर मैनेजमेन्ट आमतौर पर फैक्ट्री को चलाने की कोशिश करती है – मैनेजिंग डायरेक्टर के गिरोह की चाँदी आमतौर पर कम्पनी के चलने में होती है और क्लोजर का मतलब उनके लिये सोने के अन्डे देने वाली मुर्गी का मर जाना होता है। इसलिये मैनेजमेन्टों द्वारा सरकार - बैंकों - शेयर होल्डरों - डीलरों - मजदूरों से रियायतों के लिये खूब पापड़ बेले जाते हैं। मैनेजमेन्ट के बस से बाहर की बात हो जाने और अन्य किसी मगरमच्छ द्वारा कम्पनी को हाथ में लेने में रुचि नहीं लेने पर ही बी आई एफ आर की "मजदूर खुद चलायें" वाली स्कीम सामने लाई जाती है। बी आई एफ आर स्कीम के तहत इस कदम का मतलब होता है : सरकार, बैंकों, बिजली बोर्ड, शेयर होल्डरों, ई एस आई आदि की फँसी-डूबी रकम को निकालने के लिये मजदूर अपने फन्ड आदि के और पैसे फँसाने के साथ-साथ स्वयं छँटनी - वेतन कटौती - वर्क लोड वृद्धि की ऐसी योजना लागू करें जिसे कोई मैनेजमेन्ट रखती तो वरकर फौरन ठुकरा देते। मजदूरों द्वारा अपने हाथों अपना खून निकाल कर जोंकों को पिलाने की कोई तुक नहीं है।

फैक्ट्री क्लोजर की स्थिति में मजदूरों द्वारा फैक्ट्री पर कब्जा और फिर अपने पैसे वसूलने के लिये कम्पनी के सामान की बिक्री के लिये दृढता से कदम उठाना कारगर लगता है। यह खासकरके इसलिये कि हेरा-फेरी में आकंठ डूबे बैंक अफसर, लेबर डिपार्टमेन्ट अधिकरी और पुलिस व प्रशासनिक अफसर लफड़ों से बचने को आतुर रहते हैं और यह लोग मजदूरों के सामुहिक कदमों को भयंकर आफत मानते हैं। कानून - व्यवस्था की फूँ-फाँ की भभकियों को नजरअन्दाज कर मजदूरों द्वारा मिल-जुल कर कदम उठाने पर भयंकर लफड़े से बचने के लिये साहब लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है : मजदूरों को उनका भुगतान तत्काल करना। (जारी रहेगा) ■

जागरण वालों से निवेदन

देवियो और सज्जनो,

काफी समय से पृथ्वी पर अत्याचार दिन दूने रात चौगुने बढ रहे हैं। ऐसे में असली अवतार, खरे मसीहा के दीर्घकाल से प्रकट नहीं होने पर बड़ी संख्या में ईश्वर-अल्लाह को दर्द-भरी पुकारें समझ में आने वाली बात है। कष्ट और जलालत से लबालब इस लोक में शायद ही कोई होंगे जिनके मन के तार आपके लय, ताल और सुर में डूबे स्वरों पर झंकृत नहीं होते होंगे। मास प्रोडक्शन का जमाना है और बढता व्यवसायीकरण आपके दुख-दर्द को स्वर देते लय-ताल-सुर को भी अधिकाधिक अटपटा बना रहे हैं परन्तु आपकी बेसुरी पुकार भी सड़कों पर वाहनों तथा फैक्ट्रियों के तन-मन को कष्ट देते शोर की तुलना में स्वीकार्य है। कुम्भकर्णी नींद में सोये देवी-देवताओं को जगाने के लिये आपका माइक लगाना जायज है। अनन्त कष्टों से मुक्ति के लिये जब-तब रात-भर जागने का अतिरिक्त कष्ट उठा कर देवी-देवताओं को पुकारना भी स्वाभाविक है। परन्तु अमान्य है आप द्वारा आपकी ही तरह कष्ट और जलालत झेल रहे अपने पड़ोसियों के कष्ट बढाना। आपसे विनम्र निवेदन है कि माइकों की वाल्युम थोड़ी कम रख कर पड़ोसियों पर रहम करें। देवियो और सज्जनो, यह आपके लिये लाभदायक भी है क्योंकि आपने भी सुना है कि मनुष्यों के शापों का भी असर पड़ता है। ■

अक्टूबर अंक लेते समय **एलसन कॉटन मिल** के तीन मजदूरों ने आक्रोश-भरे शब्दों में नाराजगी जाहिर की कि मैनेजमेन्ट द्वारा महीनों से फैक्ट्री में की तालाबन्दी के बारे में हमने अखबार में कुछ नहीं लिखा। **कॉन्टिनेन्टल डिवाइसेज** की एक महिला मजदूर की शिकायत थी कि कॉन्टिनेन्टल मैनेजमेन्ट द्वारा वरकरों पर किये जा रहे अत्याचार के बारे में हम कुछ नहीं लिखते। अखबार बाँटते समय मजदूरों से बार-बार यह शिकायत हमें सुनने को मिलती है कि हम उनकी फैक्ट्री के बारे में नहीं लिखते। कृपया जान लीजिये कि हम में से कोई भी संवाददाता - पत्रकार नहीं है, हम में से कोई भी यह काम ध्याड़ी पर नहीं करता। जो जानकारी मजदूर हमें देते हैं वही हम अखबार में देते हैं। इसलिये आप अपनी बात हमें बतायें या खत डाल दें। अपनी बात छपवाने के लिये आपका पैसा खर्च नहीं होगा और जो मजदूर अपनी बात छपवाते हैं उनके नाम हम किसी को नहीं बताते। अखबार की छपाई का खर्च वे लोग अपनी आमदनी में से देते हैं जो इस काम को ठीक मानते हैं। बरसों के प्रयासों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि रुपये-पैसे के दबदबे में अखबार को फ्री बाँटना नये बराबरी के समाज के निर्माण की राह पर एक कदम है। फरीदाबाद में 14 साल के प्रयास के बाद भी हम महीने में एक बार ही अखबार छाप पा रहे हैं और दो साल से ही हम हर महीने कभी पाँच तो कभी दस हजार अखबार ही फ्री बाँट पा रहे हैं। अखबार लेते समय कई मजदूर हम से पूछते हैं कि अखबार में सहयोग के लिये पैसे किसे दें, कहाँ दें। दोहरा दें, अखबार बाँटने वालों में कोई ध्याड़ी पर नहीं है, सब यह वालेन्टरी तौर पर फ्री करते हैं – आप अखबार लेते समय किसी को भी पैसे बेझिझक दे सकते हैं। समय निकाल कर आप बाटा चौक और मुजेसर के बीच आटोपिन झुग्गियों में मजदूर लाइब्रेरी आ सकते हैं। अखबार की संख्या बढाना,पन्ने बढाना, महीने की जगह पन्द्रह दिन या हफ्ते में छापना इस पर निर्भर करता है कि ऐसा चाहने वाले कितने हैं और तन-मन-धन का कितना योग जुट सकता है। फरीदाबाद में ही प्रत्येक मजदूर महीने में एक रुपया लगाये तो हर महीने लाखों की संख्या में यह अखबार कई शहरों - देहातों में फ्री बँट सकता है। हजार मजदूर भी हर महीने अपनी बात लिखने की कोशिश करें तो अखबार की रंगत ही बदल जायेगी। फरीदाबाद में सुबह की शिफ्ट में दस जगहों पर और 6-7 फैक्ट्रियों के गेटों पर अखबार बाँटा जाता है – एक दर्जन नये लोग इसमें हाथ बँटायें तो हमें काफी राहत मिलेगी। खत डालने के लिये पता है –

मजदूर लाइब्रेरी
आटोपिन झुग्गी
फरीदाबाद – 121001

पेन्शन स्कीम

(सरकार के पेन्शन अध्यादेश के सन्दर्भ में इस अखबार के जून 1993 अंक से हम यह रीप्रिन्ट कर रहे हैं।)

प्रोविडेन्ट फन्ड - पेन्शन स्कीम पर छिड़े विवाद के सन्दर्भ में 31 मई के इकॉनोमिक टाइम्स में मद्रास के श्री पी एस नरसिम्हन का पत्र छपा है। पत्र के अनुसार इस स्कीम पर मजदूरों की राय सर्वोपरि महत्व की है लेकिन स्कीम पर सब विचार-विमर्श मजदूरों की पीठ पीछे करके नेताओं ने इसे अपने बीच एक और खेल बना लिया है।

पत्र में पेन्शन स्कीम को स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण लिया गया है। मान लीजिए कोई 30 वर्षीय आज एक हजार रुपये महीना वेतन पर नौकरी आरम्भ करता/करती है। हिसाब लगाना आसान करने के लिये यह भी मान लीजिये कि इसी एक हजार रुपये महीने पर लगातार 28 साल नौकरी करने के बाद वह 58 वर्ष की आयु में रिटायर होगा/होगी। पुराने तरीके से प्रोविडेन्ट फन्ड में हर साल एक हजार रुपये वरकर के और एक हजार रुपये मैनेजमेंट के जमा होंगे। एक रुपया सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज के हिसाब से 28 साल में यह रकम तीन लाख इक्यासी हजार तीन सौ अठान्वे रुपये हो जायेगी। पुरानी स्कीम जारी रहने

(बाकी पेज चार पर)

जबरन वसूली

मैनेजमेन्टों द्वारा मजदूरों के वेतन में से पैसे काटना और इकट्ठ करके लीडरों को देना फरीदाबाद में आम बात हो गई है। फैक्ट्री गेट के बाहर चन्दा लेना बीते जमाने की बात लगने लगी है; फैक्ट्री के अन्दर लीडरों द्वारा चन्दा लेने के दिन याद करने के लिये भी दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। मजदूरों के पक्ष में काम करने के लिये मैनेजमेन्टें लीडरों की मदद करती हैं... यह भौंडा मजाक इस कदर बढ गया है कि सस्पैन्ड वरकरों को कानूनन देय 75 परसेन्ट निलम्बन भत्ता **बाटा** मैनेजमेन्ट द्वारा देने से महीनों इनकार करने के बाद यूनियन लीडरों ने सस्पैन्ड मजदूरों की सहायता के नाम पर प्रत्येक मजदूर द्वारा दस रुपये चन्दा देने का प्रस्ताव पास किया और बाटा मैनेजमेन्ट को हर मजदूर के वेतन में से पैसे काट कर इकट्ठ करने का आवेदन दिया...

दरअसल, अपने दल्ले पालने के लिये पहले मैनेजमेन्टें अपने बही-खातों में से खर्च करती थी परन्तु अब यह खर्चे भी खुलेआम मजदूरों पर डाल रही हैं। वर्दी, जूते, बर्तन, कम्बल, अटैची, मिठाई अब मैनेजमेन्टें लीडरों के जरिये खरीदवाती हैं – ज्यादा कमीशन और घटिया सामान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठेके पर कैन्टीन भी लीडरों के लिये दुधारु गाय और मजदूरों के लिये पतली दाल रही हैं लेकिन आजकल मैनेजमेन्टें वास्तविक वेतन में ज्यादा कटौती के लिये कैन्टीन सब्सीडी पर कम खर्च के वास्ते मजदूरों को लॉलीपॉप थमा रही हैं और लीडरों को एकमुश्त भुगतान कर उनकी इस दुधारु गाय के थन बाँध रही हैं। फरीदाबाद में फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन का काम कैजुअल वरकरों और ठेकेदारों के मजदूरों से लेने का सिलसिला तेजी से बढ रहा है – अफसरों और लीडरों के लिये यह कामधेनु है : फैक्ट्री में दो महीने काम दिलाने के लिये पैसे लेना; ठेकेदार से प्रति मजदूर के हिसाब से रकम लेना। भय के भूत अथवा स्वर्ग के सब्जबाग दिखा कर परमानेन्ट मजदूरों से रक्षा कोष - संघर्ष फन्ड में 50-100 रुपये एकमुश्त लेना... इतना ही नहीं, लीडर के स्वास्थ्य के लिये **एस्कोर्ट्स** मैनेजमेन्ट ने कुछ समय पहले 50 रुपये प्रत्येक मजदूर के वेतन में से काटे थे और अब फिर 100 रुपये हर मजदूर की तनखा में से काट कर चौदह लाख रुपयों का बोरा भर कर लीडर को दिया है। और, **झालानी टूल्स** में मजदूरों को अगस्त की तनखा अक्टूबर के अन्त तक नहीं दी गई है लेकिन डेढ साल से प्रत्येक माह के वेतन में से मैनेजमेन्ट हर मजदूर के दस रुपये काट कर लीडरों को दे रही है और लीडर कर्ज दे रहे हैं मजदूरों को...

कहने को मजदूरों से वसूले पैसों का हिसाब-किताब रखने की लम्बी-चौड़ी बातें की जाती हैं लेकिन जहाँ झन्डा बदलता है वहाँ चन्दा भी चूक जाता है और जहाँ झन्डा बरकरार रहता है पर लीडर बदलते हैं वहाँ बही-खातों में जीरो मिलता है...

मैनेजमेन्ट के दल्ले और उनके लठैत व लगुये-भगुये पालने के लिये मजदूरों द्वारा स्वेच्छा से चन्दा देना अपना जूता और अपना ही सिर वाली बात होती परन्तु लाख कुप्रचार के बावजूद मजदूर बेवकूफ नहीं हैं। यह इसीलिये है कि मैनेजमेन्टें जबरन वसूली कर रही हैं। वेतन में से काटे हुये पैसे वापस माँगना मैनेजमेन्ट - लीडर गठजोड़ को चुनौती देना होता है। इक्के-दुक्के मजदूर द्वारा मैनेजमेन्ट - लीडर गिरोहबन्दी से खुली दुश्मनी मोल लेना मजदूर-पक्ष के लिये कोई कारगर औजार नहीं है और फिर इस प्रकार के कदम आमतौर पर नये लीडरों को जन्म देते हैं...

अनुभव की बात

जनरल मोटर्स की अमरीका स्थित एक कार फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन पर 22 साल काम कर चुका एक मजदूर कहता है, "फैक्ट्री में काम करने के दौरान मैंने अच्छे व लड़ाकू मजदूरों समेत बहुत ज्यादा लोगों को लीडरै बनने पर बदलते देखा है। प्रतिनिधि-नुमाइन्दे-लीडर लोग कम्पनी से डील करते हैं और यही चीज जिसका हमें बार-बार पता चला है वह यह है कि कम्पनी की सोच-विचार और हमारे प्रतिनिधियों-लीडरों की समझ एक ही हो जाती है।" (न्यूज एन्ड लैटर्स, जून 1995 अंक में।) ■

घातक चकाचौंध

कोई राजी से मजदूर नहीं बनता। नौकरी-चाकरी हम मजबूरी में करते हैं। नौकरी नहीं का मतलब रोटी नहीं हो गया है। कम्पनियों की बढ़ती गिनती और साइज के साथ छोटे-मोटे काम-धन्धे करने वालों का कचूमर निकलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। और ऊपर से बेरोजगारों की बढती तादाद... यह इसीलिये है कि नौकरी की सुरक्षा को दुनियाँ-भर में मजदूर अब बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। यह इसीलिये है कि मैनेजमेन्टों की गोल्डन शेक हैन्ड वाली वालेन्टरी रिटायरमेन्ट स्कीमें हर जगह फेल हो रही हैं। ऐसे हालात में रात को दिन कह कर ही कोई छँटनी वाली एग्रीमेन्ट की बड़ाई कर सकता है और यही मैनेजमेन्ट - लीडर गठजोड़ **केल्विनेटर एग्रीमेन्ट** के बारे में कर रहे हैं।

नई मैनेजमेन्ट केल्विनेटर का नया नाम वर्लपूल, यानि डुबो देने वाली भँवर रख रही है। स्टाफ के 750 सदस्यों को नौकरी से निकाल कर अब तीन हजार मजदूरों की नौकरियाँ डकार कर अपना नाम साकार करने के लिये वर्लपूल मैनेजमेन्ट ने चौंधियाने वाली एग्रीमेन्ट की है और जोर-जोर से नगाड़े बजा रही है क्योंकि अन्धे-बहरे मजदूरों की बलि आसान होती है।

मैनेजमेन्ट, यूनियन लीडरों और सरकारी अफसरों द्वारा मिल-बैठ कर की गई जिस एग्रीमेन्ट की बड़ाई फरीदाबाद-भर में की जा रही है उसे केल्विनेटर के किसी मजदूर ने नहीं देखा है। हमने केल्विनेटर के जितने भी मजदूरों से "बेमिसाल एग्रीमेन्ट" की कापी माँगी है उन सब ने यही कहा है कि लीडर से ही मिल सकती है परन्तु वे लीडर से माँग नहीं सकते क्योंकि एग्रीमेन्ट की कापी माँगना मैनेजमेन्ट व लीडरों, दोनों से दुश्मनी मोल लेना है।

लक्षण बता रहे हैं कि वरकर शीघ्र ही हलचल में नहीं आये तो नोट गिनने के लिये केल्विनेटर के आधे मजदूर भी नौकरी पर नहीं रहेंगे और, जिनकी नौकरी रहेगी उनके हाथ नींद में सपनों में भी प्रोडक्शन लाइन की रफ्तार अनुसार क्रियायें करेंगे। कहने को स्टाफ के 750 लोगों ने बढिया हिसाब के कारण राजी से रिजाइन किया और यही अब मजदूरों के बारे में कहा जायेगा। वैसे, स्टाफ वाला हाल होने का डर दिखा कर लीडरों ने प्रत्येक मजदूर से 50 रुपये नौकरी सुरक्षा फन्ड के नाम पर वसूले थे।

नोट :- अक्टूबर 95 में 2300 फ्रिज प्रतिदिन से बढा कर अक्टूबर 96 में 3100 फ्रिज प्रतिदिन किया जाने वाला प्रोडक्शन नवम्बर 96 में 2400 (चौबीस सौ) फ्रिज प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। इस उल्टी-पल्टी गँगा का कारण जानते हो? मेन प्लान्ट, यानि फस्ट प्लान्ट बन्द ! और ... और बचे हुये मजदूरों को अप्रैल 97 में 3150 फ्रिज प्रतिदिन बनाने होंगे !! ■

दो कुत्ते

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में एच एस ई बी वरकर्स यूनियन (हैड आफिस भिवानी) द्वारा 18 और 19 अक्टूबर को रखी दो दिन की हड़ताल बढ़ कर अनिश्चित काल तक स्ट्राइक बन गई। विगत में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के लिये जो तरीका अपनाया गया था वही तरीका हरियाणा सरकार ने इस स्ट्राइक में अपनाया : हजारों बिजली बोर्ड वरकरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, हजारों पर केस बना दिये और गिरफ्तारियों का सिलसिला चलाया। लीडरों ने 26 अक्टूबर से जत्थों में गिरफ्तारियाँ देने के लिये चन्दीगढ़ में डेरा जमाया और प्रतिदिन 250 के निर्धारित कोटा की जगह हजार-बारह सौ बिजली बोर्ड वरकर गिरफ्तारी देने लगे। एच एस ई बी वरकर्स यूनियन (हैड आफिस हिसार) हड़ताल में शामिल नहीं हुई और इसके लीडर हड़ताल के दौरान काम जारी रखने के प्रयास करते रहे।

बिजली बोर्ड के एक वरकर के अनुसार बोर्ड मैनेजमेन्ट ने दो कुत्ते पाल रखे हैं। जब-तब एक-थोड़ा गुर्राने लगता है उस समय मैनेजमेन्ट की तरफ से दूसरा भौंक कर उसे ठन्डा करने में मदद करता है। मजदूरों की कीमत पर कुर्ते-पजामे पहने दोनों कुत्ते तगड़े हैं। हालत खस्ता है तो वरकरों की।

दस हजार की बजाय इस बार हम छह हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट रहे हैं। दो हजार मजदूर अगर हर महीने दो-दो रुपये दें तो पहले की तरह दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

19 नवम्बर को सुबह दस बजे, 20 को शाम 5 बजे और 21 नवम्बर को रात 8 बजे इस अखबार के नवम्बर अंक पर मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी में चर्चा होगी। हर कोई इसमें भाग ले सकता है।

हलचल

★ 17 अक्टूबर को शाम 7 बजे 63-64 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित **हितकारी पोट्रीज** के वरकरों को पता चला कि लीडरों ने 11 प्रतिशत अभी और बाकी 11 परसैन्ट बोनस 25 जनवरी को देने का फैसला किया है। मजदूर आगबबूला हो गये। 18 को सुबह साढे आठ बजे से ही वरकर लीडरों से इस्तीफे माँगने लगे और तीन बजते-बजते मजदूर फैक्ट्री गेटों पर इक्ट्ठे हो गये तथा किसी को बाहर नहीं जाने दिया। पाँच बजे सब वरकर फैक्ट्री के अन्दर पार्क में जमा हो गये। 22 प्रतिशत बोनस, हर महीने दस तारीख तक तनखा और 5 साल से रुके वर्दी-जूतों के बारे में फैसला करने के लिए मजदूरों ने कम्पनी चेयरमैन को पार्क में आ कर बात करने को कहा। 6 बजे चेयरमैन कृष्ण कपूर मजदूरों के बीच आये और हाथ जोड़ कर कम्पनी के दलदल में फँसे होने का रोना रोया तथा आश्वासन दिये। प्याली मजदूर यूनियन लीडरों को वी आई पी कहते हैं और इन्हें मैनेजमेन्ट के पर्दों के तौर पर लेते हैं।

★ दिवाली पर 24 सैक्टर स्थित **हिन्दुस्तान वायर** फैक्ट्री मैनेजमेन्ट ने लीडरों के जरिये मिठाई खरीदवाई। ज्यादा कमीशन के चक्कर में मिठाई इतनी खराब आई कि मजदूरों ने मिठाई के डिब्बे मैनेजमेन्ट को वापस दे दिये।

★ दिवाली पर ही एस्कोर्ट्स ग्रुप के **फोर्ड प्लान्ट** में ज्यादा कमीशन के चक्कर में फफूँद लगी मिठाई मजदूरों को दी गई। 600 से ज्यादा मिठाई के डिब्बे वरकरों ने मैनेजमेन्ट को वापस दे दिये।

★ मैनेजमेन्ट द्वारा जुलाई में दस दिन की तालाबन्दी कर 18 दिन का वेतन काट लेने के बाद से **ईस्ट इंडिया कॉटन मिल** के मजदूरों ने अधिकारियों से दुआ-सलाम बन्द कर दी है। मैनेजमेन्ट ने दिवाली पर इस साल मजदूरों को मिठाई और बर्तन नहीं दिये। 20 अक्टूबर को रात 11 बजे फैक्ट्री गेट पर ठसाठस भरी एम्बुलैन्स और एक मेटाडोर के बारे में पूछने पर मजदूरों ने बताया कि ईस्ट इंडिया मैनेजमेन्ट डेली वेज पर भरती करके लोगों को दाल फ्राई गिरोह के साथ गाजियाबाद में अपनी ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री में हड़ताल तोड़ने के लिये भेज रही है।

उल्लेखनीय कदम

24 सैक्टर स्थित एक छोटी फैक्ट्री। दिवाली पर मजदूरों ने मिठाई के साथ बर्तन डिमान्ड किये। बर्तन नहीं दिये गये। मजदूरों ने एडवान्स और मिठाई के डिब्बे लिये। हर वरकर ने पैसे जेब में रखे और मिठाई के डिब्बे वापस वहीं रख दिये।

मजदूरों के ऐसे सामुहिक विरोध हमारे-आपके लिये नरसिम्हा राव की पूँछ और आडवाणी की मूँछ से अधिक महत्वपूर्ण हैं। मिल-जुल कर आप जो कदम उठाते हैं उनकी जानकारी हमें देंगे तो हम आपके अनुभवों को अन्य मजदूरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।

पेन्शन स्कीम....(पेज तीन का शेष)

पर रिटायर होने पर उस वरकर को 3, 81, 398 रुपये प्रोविडेन्ट फन्ड के मिलेंगे। इसी उदाहरण वाले वरकर को नई स्कीम के मुताबिक रिटायर होने पर 1, 90, 699 रुपये मिलेंगे और बाकी 1, 90, 699 रुपये पेन्शन स्कीम चलाने में काम आयेंगे। सरकार की पेन्शन स्कीम के अनुसार उस वरकर को 428 (चार सौ अठाइस) रुपये महीना पेन्शन मिलेगी। एक लाख नब्बे हजार छह सौ निन्यानवे रुपये का एक रुपया सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज की दर से ही ब्याज एक हजार नो सौ छह रुपये निन्यानवे पैसे प्रतिमाह होता है ! और पेन्शन स्कीम में तो मूलधन वापस मिलने जैसी कोई बात है ही नहीं।

इसीलिये सरकार "मजदूरों की भलाई वाली" इस स्कीम को स्वीकार करना अथवा रिजेक्ट करना मजदूरों पर नहीं छोड़ सकती। पेन्शन स्कीम को कम्पलसरी बनाने का कानून संसद में है। ■

फैक्ट्रियों में तथा बस्तियों में सामुहिक कदमों की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाना हमारे लिये खुशी का काम है। अगर आपके पास ऐसी जानकारी है तो वह हमें दें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 **पोस्टल रजिस्ट्रेशन** L/HR/FBD/73
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स बी – 548 नेहरू ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।